Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के प्रभाव की खोज

डॉ. जी. एल. खांगोडे* शिवानी जायसवाल**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शोध पत्र में वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच भारतीय आर्थिक विकास पर एमएसएमई के संभावित प्रभाव का पता लगाया गया है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और उनकी प्रमुख विशेषताओं का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतीय आर्थिक विकास को और अधिक प्रगतिशील तथा परिणामोन्मुखी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरते स्तंभ हैं और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के साथ गरीबी में कमी लाने तथा स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एमएसएमई के लाभ पर ध्यान केंद्रित करने और स्थानीय उद्यमों को बढ़ाकर रोजगार सृजन में वृद्धि करने और साथ ही नौकरियों और निवेश के संदर्भ में एमएसएमई के विकास और प्रदर्शन का आंकलन करने का प्रयास करता है।

शब्द कुंजी – एमएसएमई, आर्थिक विकास, उद्यमिता, स्थानीय उद्यम, रोजगार।

प्रस्तावना – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। एमएसएमई को भारत सहित सभी विकासशील देशों के लिए 'प्रगति का इंजन' भी कहा जाता है। यह प्रचुर मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराते हैं तथा शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। यह समाज के सबसे कमजोर और गरीब लोगों के लिए बहुत काम करता है। एमएसएमई औद्योगिकीकरण में मदद करते हैं, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, कम निवेश के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इस पत्र का उद्देश्य भारत देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई उद्यमों के प्रभाव का पता लगाना है। एमएसएमई क्षेत्र हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है और यह समावेशी और वितरित विकास हासिल करने का एक अच्छा साधन है। वर्तमान भारत सरकार ने एमएसएमई के संवर्धन के लिए कई सकारात्मक पहल की हैं, जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना, पीएमआरवाई आदि।

भारत सरकार ने एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के 14 वर्ष बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई को पुन: परिभाषित किया है। एमएसएमई को परिष्कृत करने का प्राथमिक उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बनाना, अधिक निवेश आकर्षित करना और एमएसएमई क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करना था। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार, एमएसएमई मंत्रालय ने अब क्षेत्र को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खुदरा और थोक व्यापारी दोनों व्यापार को एमएसएमई के तहत शामिल किया है। एमएसएमई के अंतर्गत ऐसे समावेशन के साथ, मंत्रालय का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के तहत बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के सीमित उद्देश्य के लिए था। यह पेपर एमएसएमई की सहायता से भारत के आर्थिक विकास की जांच करेगा, कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा करेगा और एमएसएमई के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का आंकलन करेगा।

इसके अतिरिक्त, यह शोध पत्र देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, निष्कर्षों के आधार पर, भविष्य के अनुसंधान के लिए सुझाव भी प्रदान करेगा, ताकि भारतीय आर्थिक प्रणाली में अधिक सकारात्मक इष्टतम परिणाम सुनिश्चित किया जा सके।

साहित्य की समीक्षा :

साहित्य समीक्षा का उद्देश्य भारतीय आर्थिक विकास पर एमएसएमई के प्रभाव का पता लगाना है। साहित्य समीक्षा में वर्तमान परिदृश्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वर्तमान समझ पर चर्चा की जाएगी। यह विषय पर आगे के शोधा के लिए वर्तमान साहित्य का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

श्रीनिवास (2013) ने एमएसएमई के प्रदर्शन और भारत की आर्थिक वृद्धि में उनके योगदान का विश्लेषण किया, एमएसएमई में उद्यमों की संख्या और रोजगार की पहचान की और निष्कर्ष निकाला कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में एमएसएमई की बीमारी और पुनर्वास (2005) लेखक का मानना है, कि – एमएसएमई कई कारणों से किसी क्षेत्र में विफल हो जाएंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने भारत के पहले से ही कमजोर बुनियादी ढांचे को और भी अधिक कमजोर कर दिया है, जिससे लघु उद्योगों के उत्पादन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। असफलता के अनेक कारण हैं, हालांकि, उनमें से सभी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं हैं। ज्ञान की कमी, उपलब्ध संसाधनों, योग्य श्रमिकों या यहां तक कि मालिक की ओर से प्रेरणा भी व्यवसाय की असफलता के संभावित कारण हैं। विफलता का कारण चाहे जो भी हो, व्यवसाय के पास अपनी रुग्णता 'घोषित' करने के लिए कुछ प्रकार के संसाधन अवश्य होने चाहिए। भारत में, यह तंत्र क्या है, यह अपेक्षाकृत अस्पष्ट है, तथा वर्तमान प्रगति के बावजूद, इसने अनेक अकुशलताएं छोड़

दी हैं।

संजीव कुमार डे (2014) एमएसएमई के महत्व को हाल के वर्षों में विकसित और विकासशील दोनों देशों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों जैसे कि रोजगार, उत्पादन, निर्यात को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता दी गई है। यह किसी भी देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि - यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत योगदान देता है।

उद्देश्य :

1. भारत में एमएसएमई के प्रदर्शन और उनकी विकास संभावनाओं का विश्लेषण करना।
2. भारत में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं पर विचार करना
3. देश में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के संबंध में एमएसएमई के परिणाम का मूल्यांकन करना।
4. एमएसएमई योजना और नीतियों के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन करना।
5. रोजगार और निवेश के संदर्भ में जमीनी स्तर की स्थितियों की जांच करना।

अनुसंधान क्रियाविधि - यह शोधा द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें विषय-वस्तु के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षणों और साहित्य की जांच की मुख्य मदद ली गई है। अधिकांश आंकड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2017 से 2022 की वार्षिक रिपोर्ट से एकत्र किए गए थे। अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए डेटा विभिन्न लेखों और प्रकाशित पत्रिकाओं से भी एकत्र किया गया है।

परिणाम :-

भारत में एमएसएमई का प्रदर्शन -

(क) किसी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के प्रदर्शन को मापने का मतलब देश के सकल घरेलू उत्पाद में उस क्षेत्र का योगदान है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान नीचे दिया गया है -

तालिका क्रमांक 1: एमएसएमई का विकास प्रतिशत (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक)

क्र.	वर्ष	GDP %	कमी / वृद्धि दर
1.	2017-18	29.25	आधार वर्ष
2.	2018-19	29.69	+1.50 %
3.	2019-20	30	+1.04%
4.	2020-21	26.83	-10.57%
5.	2021-22	30	+11.81%

स्त्रोत - एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22

एमएसएमई का एक और सकारात्मक प्रभाव रोजगार सृजन पर है। एमएसएमई ने रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार 5 वर्षों में रोजगार सृजन में शीर्ष 10 राज्यों का विश्लेषण, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का विवरण -

तालिका क्रमांक 2

S.	State	2017 -18	2018 -19	2019 -20	2020 -21	2021 -22
1	Uttar Pradesh 14%	546021	361761	361021	800146	847687
2	West Bengal 14%	152774	141722	264024	251498	555317
3	Tamil Nadu 8%	601788	429314	501816	936255	854219
4	Mahar ashtra 8%	700212	606815	634334	1392726	1123000
5	Karnataka 6%	369606	291854	327723	585031	773214
6	Bihar 5%	183887	177074	191091	441429	567241
7	Andhra Pradesh 5%	173898	117225	123951	266068	370771
8	Gujrat 5%	418450	275241	282037	521524	373447
9	Rajas than 4%	378607	226675	249819	578555	820332
10	Madhya Pradesh	174341	151942	143150	341260	412845

एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार 5 वर्षों में रोजगार सृजन में शीर्ष 10 राज्यों का विश्लेषण, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का विवरण।

साहित्य समीक्षा, द्वितीयक समंक, सर्वेक्षण, नमूने, शोध पत्र, पुस्तकें, मुद्रण मीडिया आदि की सहायता से हमने पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई के सामने आई कुछ चुनौतियों का पता लगाया जैसे -

(क) पर्याप्त ऋण का अभाव
(ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा
(ग) खराब बुनियादी ढांचा
(घ) उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव
(ग) संसाधनों की अनुपलब्धता
(इ) कार्यशील पूंजी की कमी

एमएसएमई को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहल की जा रही हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) देश में एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना (एएसपीआईआरई), स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया शामिल हैं।

कुछ और पहल -

1. एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण
2. एमएसएमई सहित व्यापार के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का कोलैटरल मुक्त स्वचालित ऋण
3. एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की

इक्विटी निवेश

4. एमएसएमएस के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड
5. व्यापार में आसानी के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण
6. 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं, इससे एमएसएमई को मदद मिलेगी।
7. प्रत्येक बीतते वर्ष में बजटीय व्यय में वृद्धि , रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एमएसएमई के लिए बजट आवंटन दोगुना से अधिक होकर 15700 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2020-21 में यह 7572 करोड़ रुपये था।

यहां हमने एमएसएमई के पिछले 5 साल के बजट आवंटन को दिखाया है-

तालिका क्रमांक 3: देश में एमएसएमई का बजट आवंटन (वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की स्थिति)

क्र.	वर्ष	बजट (करोड़ मे)	प्रतिशत
1.	2017-18	6481	14.96%
2.	2018-19	6552	15.13%
3.	2019-20	7011	16.18%
4.	2020-21	7572	17.48%
5.	2021-22	15700	36.25%
	कुल	**43316**	**100.00**

स्रोत - एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22

निष्कर्ष - एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरा है। रोजगार और आय सृजन में एमएसएमई का योगदान बहुत बड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एमएसएमई के पिछले दो वर्ष पूरी तरह से उत्कृष्ट रहे, लेकिन आगामी वर्ष में एमएसएमई निश्चित रूप से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्योग को नए युग की प्रौद्योगिकी को अपनाने पर अधिक धयान देना चाहिए, जिसमें अधिक डिजिटलीकरण प्रणाली शामिल है। सरकार द्वारा प्रदान की गई लाभकारी योजनाओं में तेजी लाने और जमीनी स्तर के उद्यमों का समर्थन करने की भी आवश्यकता है क्योंकि छोटे उद्यम केवल छोटे शब्द के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन वे ही हैं जो विकास को बढ़ावा देने के साथ अर्थव्यवस्था में बहुत प्रगति में योगदान करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अमुथा, डी., भारत में उद्यमिता और आर्थिक विकास के सृजन में एमएसएमई की भूमिका (27 मार्च, 2022) SSRN पर उपलब्ध https://ssrn.com/abstract=4076260
2. जंजुरे प्रियदर्शिनी, भारत में एमएसएमई का विकास और भविष्य की संभावनाएं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड साइंस (आईजेएईएमएस) (वॉल्यूम-4, अंक-8, अगस्त-2018)
3. गाडे सुरेन्द्र, एमएसएमई की आर्थिक वृद्धि में भूमिका: भारत के परिप्रेक्ष्य पर एक अध्ययन (शुद्ध और अनुप्रयुक्त गणित का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल)
4. श्रीनिवास, के.टी. (2013) समावेशी विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका (इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट रिसर्च, 3, 57-61)
5. सानू, एमडी साहनेवाज़, भारत के कुल निर्यात और जीडीपी वृद्धि में एमएसएमई का योगदान: सह-एकीकरण और कारणता परीक्षणों से साक्ष्य (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/107892/ एमपीआरए पेपर नंबर 107892)
6. सुधा वेंकटेश, कृष्णवेणी मुथैया, एसएमई के लिए विकास के निर्धारकों पर एक अध्ययन - सर्वो स्टेबलाइजर विनिर्माण इकाइयों के संदर्भ में।
7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-22
8. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1886709
9. https://pib.gov.in/PressReleasePage-aspx?PRID=1881704
1. https://pib.gov.in/PressReleasePage-aspx?PRID=1778406
11. लेख- एमएसएमई के पास 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की कुंजी है। (https://www.business-standard.com/article/opinion/msmes-hold-the-key-to-5-trn-economy-122110600679_1-html)

****